गई थी जिससे हजारों श्रमिकों की जानें खतरे में पड़ गई थीं ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार खान-सुरक्षा विभाग के अधिकारियों और खान प्रबंधकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) दिनांक 13-14 जुलाई, 1986 की रात में भारी वर्षा के कारण बिजुरीह खान के लोहसरा इन्क्लाइन में विकसित कार्यस्थलों पर छिछले कवर एरिया में 25X15 मीटर का पाट होल बन गया था । वर्षा का पानी पाट-होल के जरिए भूमिगत क्षेत्र में घुसने लगा परन्तु कोई मौत नहीं हुई क्योंकि प्रभावित क्षेत्र के नीचे या उसके आसपास कोई कामगर काम पर नहीं लगाया गया था दिनांक 14 जुलाई, 1986 की प्रातः सतह पर एक बांध बनाया गया ताकि वर्षा का पानी पाट-होल की ओर नहीं जाकर दूसरी ओर जाए । जो पानी भूमिगत खान में एकत्र हो गया था, उसे भी पंप से बाहर निकाल दिया गया । चूंकि यह दुर्घटना कुछ ही घंटों में 76 मि.मी. तक असाधारण भारी वर्षा होने से हुई और यह ऐसी घटना थी जिस पर प्रबंधमंडल का नियंत्रण नहीं था, इसलिए कर्तव्य की उपेक्षा के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उन किसानों के परिवारों के सदस्यों को रोजगार, जिनकी भूमि का कोयला-खनन कार्य हेतु अधिग्रहण किया गया है

1787. **श्री शरद यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी करके यह निदेश दिया है कि उन किसानों के परिवार के किसी भी सदस्य को रोजगार न दिया जाए जिनकी तीन एकड़ से कम भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश आदिवासी किसानों के पास तीन एकड़ से भी कम भूमि है, और यदि हां, तो क्या सरकार परिपत्र में संशोधन करने का विचार रखती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं। कोयला विभाग की यह नीति है कि यदि संबद्ध परियोजना में रोजगार की गुंजाइश हों तो नौकरी देने में भू-विस्थापितों को वरीयता दी जाए। सरकार ने आदेश जारी करके सरकारी उपक्रमों द्वारा अधिग्रहीत भूमि के मालिकों को, उनसे अधिग्रहीत भूमि के आकार का विचार किए बिना रोजगार देने की पुरानी कार्य प्रथा बिल्कुल समाप्त कर दी है। फिर भी ऐसी प्रत्येक परियोजना में—जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है—भूवंचितों के लिए पुनर्वास के अन्य उपाय किए जाएंगे ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आदिवासी किसानों के स्वामित्व वाली भूमि के एकड़ों की संख्या का कोई महत्व नहीं है।

Conference of Power Ministers

1788. SHRI K. VASUDEVA PANICKER: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a conference of Power Ministers of States was held in Delhi on 14th July, 1986 to discuss augmentation of power generation and supply in different States; and

(b) if so, what are the details of the discussions held and the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) and (b) A Conference of Power Ministers of some States was held in Delhi on 15th July, 1986. Discussion was held on various matters which have a bearing on improving the power availability such as commissioning of new projects, better utilisation of existing capacity, renovation and modernisation programme etc. The main conclusions reached were that these States would pay greater attention to expeditious commissioning of on-going power projects, early stabilisation of newly commissioned units, improving the utilisation of the existing capacities of thermal power stations to improve the PLF, accelerate the pace of progress of renovation and modernisation of Thermal Power Stations and reduction of transmission and distribution losses.

Oil exploration and exploitation

1789. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the Oil and Natural Gas Commission has prepared a long term plan for oil exploration and exploitation to move ahead towards the goal of self-sufficiency; and

(b) if so, what are the details in regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) and (b) ONGC had prepared a 20 year perspective plan for 1985—2005. This envisaged a total production of 100 million tonnes of oil and oil equivalent of gas by 2005 A.D. Of the various alternatives developed, the 3 preferred alternatives envisaged oil-production of 50, 55 and 60 million tonnes respectively by 2005 A.D.; the balance being made up by production of gas. These alternatives aimed at self-sufficiency in oil in the range of 67 per cent to 80 per cent.

Plant Load Factor

1790. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what is the national average of plant load factor;

(b) what are the names of the States which have achieved this national average and of those which have yet to achieve it;

(c) what is the average percentage in each of these States, which have not achieved it; and

(d) what measures have been taken to improve the performance of power stations and minimise transmission losses?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) The all India average plant load factor of thermal power stations during 1985-86 was 52.4 per cent.

(b) and (c) The statewise details of plant load factor during 1985-86 are given in the enclosed Statement. (*See* below).

(d) The measures taken to improve the performance of thermal power stations include implementation of the centrally sponsored renovation and modernisation scheme, improvement in quality of coal, upgradation of the skills of operation and maintenance staff, early stabilisation of newly commissioned units and reduction in the outage periods of thermal units.